

## देश के विकास में मीडिया की भूमिका का एक अध्ययन

डॉ. आशुतोष मंडावी\*

### प्रस्तावना

विकास का शाब्दिक अर्थ प्रसार या फैलाव होता है। जब हम जनसंचार के संदर्भ में विकास शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ बहुत अधिक व्यापक हो जाता है। जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को विकास से जोड़ा जा सकता है। व्यक्ति के बौद्धिक विकास की बात चलती है, तो देश में शिक्षा, संचार-माध्यम तथा साहित्य के क्षेत्र में हो रही गतिविधियाँ हमारे सामने होती हैं। उसके सांस्कृतिक विकास, ललित कलाओं –कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच आदि के विकास के लिए हो रहे कार्यों का हवाला दिया जाता है। सामाजिक विकास के संदर्भ में बदलाव, बदलते सामाजिक संबंधों और मूल्यों का उल्लेख किया जाता है। भौतिक विकास को उद्योग, कृषि, औद्योगिकी, तकनीक, व्यापार आदि के विकास से जोड़ा जाता है। संक्षेप में, व्यक्ति की खुशहाली के समाचार या विकास की मुख्यधारा से कटे हुए लोगों की खबरे विकासात्मक जनसंचार का विषय बनती हैं।

विकास पत्रकारिता का ऐसा क्षेत्र है, जिसे आजादी मिलने के बाद समाचार पत्रों को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए था जो कि नहीं हो पाया। राष्ट्र को सजाने संवारने के उद्देश्य से राजनीतिज्ञों के साथ मीडिया जगत की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी। शुरु के कुछ वर्षों में ऐसी स्थिति रही भी लेकिन उसके बाद राजनीतिज्ञों का जो महत्व मीडिया जगत ने स्वीकार किया उसके बाद तो आज हालत ऐसी बन गयी कि चाहें समाचारपत्र को किसी भी छोर से पढ़ना शुरु करें सिवाय राजनीति के और कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा।

सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही समान रूप से समाचार पत्र के कालमों को घेरें पड़े हैं। राजनीतियों के वक्तव्य, भाषण, आरोप प्रत्यारोप आन्दोलन आदि सभी को समाचार जगत प्रमुखता से प्रकाशित करता रहा है। दूसरे नम्बर पर हिंसा तथा अन्य जघन्य अपराधिक घटनाएं तीसरे या कभी-कभी चौथे स्थान पर विकास संबंधी कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों को भी समाचार पत्रों के कालम में स्थान मिल जाता है। विकास संबंधी समाचारों से कहीं अधिक प्रमुखता सिनेमा जगत के पुरुष और महिलाओं को मिल रहा है। शर्म की बात तो यह है कि बहुत सी पत्र पत्रिकाओं ने तो गपशप शीर्षक से नियमित कालम शुरु किये हुए हैं लेकिन विकास संबंधी रचनात्मक गतिविधियों के लिए स्थान नहीं है।

विकासात्मक पत्रकारिता या विकासात्मक समाचारों की उपादेयता व्यापकता और भूमिका को रेखांकित करते हुए द्वितीय प्रेस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि- “विकास संबंधी रपट में सही और गलत काम की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए। उसमें आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न स्थानों पर सफलता और विफलता के कारणों की छानबीन होनी चाहिए। हर व्यक्ति यह जानना चाहता कि चारों ओर ऐसा क्या घटित हो रहा है जिसका प्रभाव उस पर पड़ता है या पड़ सकता है। उसके जीवन में सुधार या परिवर्तन के लिए भी कोई संभावना बन रही है या बनने की प्रक्रिया में है। ऐसी बातों को जानने की भी उसमें जिज्ञासा होती है जो भले ही सनसनीखेज और रोमांचक न हो परंतु उसके जीवन में बदलाव का संकेत देती हो। ऐसे समाचार जो स्थितियों में बदलाव के प्रयत्नों एवं उनकी

\* विभागाध्यक्ष, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।

सफलता विफलता पर प्रकाश डाले किसी भी समाचार पत्र या माध्यम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आमतौर से विकासात्मक समाचारों का अर्थ उन समाचारों से लिया जाता है जो खेती उद्योग आदि के क्षेत्र में विकास के आकड़े प्रस्तुत करते हैं। परंतु वस्तुतः यह विकास का मात्र एक पक्ष है। दूसरा और अधिक वास्तविक पक्ष यह जानना है कि विभिन्न विकास योजनाओं के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव तथा विकास के क्रम में कौन आगे बढ़ा और कौन पीछे छूट गया है।”

वर्तमान समय में मीडिया का क्षेत्र एवं परिधि बहुत व्यापक हो गया है। उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रही हलचलों, संभावनाओं पर विचार कर एक नई दिशा देने का काम मीडिया के क्षेत्र में आ जाता है। मीडिया जीवन के प्रत्येक पहलू पर नजर रखे हुए है। इन अर्थों में उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। मीडिया तमाम जनसमस्याओं एवं सवालों से जुड़ी होती है, समस्याओं को प्रशासन के सामने प्रस्तुत कर उस पर बहस के लिए प्रेरित करती है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में आज मीडिया की महत्ता स्वीकार की जा रही है। आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक, विज्ञान, कला सभी क्षेत्र मीडिया के दायरे में हैं। इन संदर्भों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीडिया का महत्व खासा बढ़ गया है। नई आर्थिक नीतियों के प्रभावों तथा जीवन में कारोबारी दुनिया एवं शेयर मार्केट के बढ़ते हस्तक्षेप ने इसका महत्व बढ़ा दिया है।

अर्थव्यवस्था प्रधान युग होने के कारण प्रत्येक प्रमुख समाचार-पत्र दो चार पृष्ठ आर्थिक गतिविधियों के लिए आरक्षित कर रहा है। इसमें आर्थिक जगत से जुड़ी घटनाओं, कम्पनी समाचारों, शेयर मार्केट की सूचनाओं, सरकारी नीति में बदलावों, मुद्रा बाजार, सराफा बाजार एवं विविध मण्डियों से जुड़े समाचार छपते हैं।

जैसा कि हमें विदित है भारत एक ग्रामीण एवं संस्कृति प्रधान देश है। हमारी कुल जनसंख्या का बीस से पच्चीस प्रतिशत भाग ही शहरों में है जबकि शेष पचहत्तर से अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। आजादी से लेकर अब तक सरकार ने गांवों के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। जिसे क्षेत्रीय समाचार पत्रों ने विस्तार से छापा है, और ऐसे समाचारपत्रों के माध्यम से लोगों को इस बात की जानकारी भी मिली है। भारत में कुछ ऐसे बड़े समाचारपत्र भी हैं, जिन्होंने 'कृषि संवाददाता' नियुक्त कर रखे हैं। लेकिन ये संवाददाता अपना कार्यक्षेत्र शहरों तक ही सीमित रखते हैं। ग्रामीण अंचलों में जो तेजी से विकास नहीं हो सका, उसका एक मात्र कारण गरीबी नहीं है, बल्कि अज्ञानता की वे जंजीरें भी हैं जिन्होंने वहां के लोगों को विकास की ओर बढ़ने से रोकने में सबसे बड़ी बाधा पेश कर रखी है और लकीर के फकीर बने हुये हैं। गरीबी और अज्ञानता की दुधारी तलवारों के बीच फसे ग्रामीण अंचल आज वह सब कुछ प्राप्त नहीं कर सके जिसके वे सही अर्थों में हकदार हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता सबसे बड़ी यह होती है कि पत्रकार और साहित्यकार उनके बीच जाकर उनके कष्ट और अनुभवों को प्रकाश में लाए, जिससे विकास से संबद्ध लोगों का ध्यान उनकी ओर जाए क्योंकि विकास पत्रकारिता के लिए क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

ग्रामीण अंचलों में अज्ञानता के कारण विकास होना तो बहुत दूर की बात है वहां तो आम जीवन में इतने कष्ट आते हैं, कि लोग उसी कुचक्र से अपने आपको नहीं बचा पाते हैं। जिस समाज में किसी महामारी का कारण भूत-प्रेत माने जायें अथवा किसी एक की बीमारी को दूर करने के लक्ष्य से किसी एक मासूम की हत्या तक कर डाली जाये तब ऐसे समाज में विकास की दिशा कहां से और कैसे पहुंचेगी ? यह एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे कुचक्रों को ध्वस्त करने के लिए टिकाऊ विकास की जरूरत है। जो कि विकास पत्रकारिता के माध्यम से ही दूर हो सकता है। ऐसे समय में यदि समाचार-पत्र का साथ इन ग्रामीणों को मिल जाये तो इनको उचित राह मिल सकता है। और केवल उनको एक ही क्षेत्रों में नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों में जैसे – सामाजिक बुराइयों, धार्मिक प्रवचन, राजनीति के छल-कपट, राजकीय चक्रव्यूह, आर्थिक दुरावस्था तथा समाजद्रोही तत्वों के दुश्कृत्यों की पोल खोलने, उनसे बचने, सचेत रहने तथा विपत्ति पड़ने पर किसी ढंग से निकलने की शिक्षा देने का दायित्व भी आज का मीडिया महत्वपूर्ण तरीके से निभा सकता है।

प्रश्न यह है कि जब तक व्यक्ति लगातार गांव में किसानों के साथ रहकर आवश्यकताओं और परेशानियों को नहीं समझता है। तब उन्हें दूर करने के लिए वह ठोस कदम उठाने की स्थिति में नहीं आ

सकता। विकास की खुशबू को गांव गांव पहुंचाने के लक्ष्य से बहुत पहले भारत सरकार ने सबसे बड़े-बड़े मंत्रालयों जैसे कृषि, रेल, समाज कल्याण, योजना आदि के मुखपत्रों का प्रकाशन शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए योजना मंत्रालय के अधीन "योजना" नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया जो आधा दर्जन भाषाओं में छपनी शुरू हुई। कृषि मंत्रालय की पत्रिका "खेती" हिन्दी में तथा अंग्रेजी में "इण्डियन फार्म जनरल" तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में "कुरुक्षेत्र" इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग की एक पत्रिका का अलग से प्रकाशन आरम्भ हुआ। भारत सरकार ने सभी महत्वपूर्ण विभागों की गतिविधियों की आवश्यक जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाने के लक्ष्य से साप्ताहिक पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं आरंभ की वे सभी हर दृष्टि से सफल सिद्ध हुई हैं।

एक बात और देखने में आयी है, कि कुछ राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों की विशेष रुचि अभी तक विकास की ओर नहीं हो सकी है। कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जिनके कालम ही क्या उनके पन्ने उन सामाचारों से भरे हुए होते हैं जो महानगरों के भव्य समारोह पर आधारित होती है। यह एक आम मान्यता है, कि अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्रों की तुलना में हिन्दी तथा अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में विकास पत्रकारिता को कहीं अधिक स्थान प्रदान किया है। 'राजस्थान पत्रिका' का अध्ययन करने से तो यह संकेत भी मिलता है कि समाचार पत्र के संपादक ने एक संवाददाता की जिम्मेदारी ही यह लगा दी थी, कि वह हर सप्ताह ग्रामीण अंचलों की दौरे से लौटकर एक रपट देंगे। काश कि ऐसा प्रयास देश के अन्य समाचार पत्र भी कर पाते।

विकास पत्रकारिता के क्षेत्र में वहीं लोग अधिक सफल सिद्ध होंगे जिनके सीने में उपेक्षित तथा अविकसित क्षेत्रों के प्रति विशेष हमदर्दी हैं। जिला मुख्यालयों से लेकर प्रदेश अथवा राष्ट्रीय मुख्यालयों में बैठे लोग विकास पत्रकारिता को आगे नहीं बढ़ा पायेंगे चूंकि ग्रामीण अंचल जहां विकास की बहुत संभावनायें हैं। वहां जाकर जो भी पत्रकार थोड़ा बहुत कार्य करके वहां की समस्याओं के प्रति समाज और सरकारी तंत्र को जानकारी उपलब्ध कराता है। जो प्रशंसनीय कहा जाता है, और बहुत सी संस्थाएं उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी करती हैं। इस क्षेत्र में आवश्यकता इस बात की है, कि अधिक से अधिक संस्थानों को आगे आना चाहिए। कलकत्ता और दिल्ली से एक साथ प्रकाशित 'स्टैटमैन' तथा देश के कुछ चुनिंदा समाचार पत्रों ने एक प्रशंसनीय कार्य यह किया है, कि जो पत्रकार ग्रामीण अंचलों की समस्या को लेकर अच्छा लेख लिखेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा इन संस्थाओं ने यह कार्य शुरू करके निश्चय ही विकास पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया है।

पिछले कुछ वर्षों में और कोरोना काल की परिस्थितियों के कारण देशभर में करीब 5 हजार से अधिक पत्रकारों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। इसके कई कारण गिनाये जा सकते हैं परंतु इसका सबसे बड़ा कारण मीडिया का बाजारवाद के प्रति बढ़ती आस्था है। आज मीडिया विज्ञापन, बालीवुड और कारपोरेट घराने तक सीमित हो गया है। अधिकतर अखबारों में आज भी कृषि तथा आम जनता से जुड़े मुद्दों को कवर करने के लिए पूर्ण कालिक पत्रकार नहीं है। यहां तक कि अंग्रेजी के कुछ बड़े अखबारों में तो रिशेसन, आर्थिक मंदी के इस्तेमाल पर रोक लगी है। कारपोरेट जगत ने एक तरह से मीडिया का अपहरण कर लिया है। आज मीडिया में आदिवासियों और दलितों का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। आज भुखमरी, गरीबी, नक्सली हिंसा के सवाल गौण होकर रह गये हैं। आज नक्सलवाद चरम पर है देश में इस पर बहस तो खूब हो रहे हैं राष्ट्रीय गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं कि आखिर इन सबका निदान कब तक संभव है।

आज अगर हम विकास की बात करते हैं तो उस विकास में सिर्फ सिमित लोगों का विकास ही शामिल है, संपन्नता की पहुंच सिर्फ कुछ ही लोगों तक सिमित है और देश की बाकी जनता उसी बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर है, देश की आजादी के 70 से अधिक वर्ष पूर्ण करने के बाद भी साक्षरता का लक्षित दर अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है, अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार द्वारा जो उद्योग-धंधे स्थापित किये जा रहे हैं उनमें प्रभावित ग्रामीणों व विस्थापित परिवारों को प्रदान की जाने वाली मुआवजा राशि की बात हो या विस्थापित परिवार के सदस्यों को नौकरी का मुद्दा हो या फिर विस्थापित परिवार के सदस्यों के शेयर होल्डिंग तय करने की बात हो इस पर मीडिया के माध्यम से सरकार को सच्चाई अवगत कराने की जरूरत है तभी सरकार इन

मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर पायेगी। क्योंकि किसी भी समुदाय के व्यक्ति के लिए आत्मसम्मानपूर्वक जीवन-यापन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ आत्मसम्मान भी जरूरी है। ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों की इस कड़वी सच्चाई को मीडिया के माध्यम से शासन-प्रशासन तक अवगत कराने की जरूरत है।

हमारा देश सांस्कृतिक वैशिष्ट्यता वाला देश है जहां की संस्कृति अपने आप में विशिष्टता लिए हुए है यहां के लोकनृत्य, लोकगीत, चित्रकला तथा लोककला, शिल्पकला आदि को तथा उनसे जुड़ी तमाम विधाओं के साथ सहेजने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोककलाओं को बचाना है और उन्हें जीवनोपयोगी रखना है तो उनके साथ जुड़े संस्कारों को भी बचाना होगा, तभी लोककलाओं को उसकी आत्मा के साथ बचाया जा सकता है। तभी सांस्कृतिक वैशिष्ट्यता को संरक्षित करने में हम सफल हो पायेंगे।

पारंपरिक लोककलाओं, लोकनृत्यों व लोकगीतों के विकास तथा संवर्धन हेतु हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में स्थान देने की जरूरत है, तथा विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी गोंडी, हल्बी, भतरी जैसी बोलियों को संरक्षित करने भाषा व लोककला संस्थान स्थापित करने के प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्राचीन बोलियां, ये लोककलाएं, ये नृत्य, ये चित्रकला तथा मूर्तिकला हजारों वर्षों के अनुभवों को अपने में संचित तथा समाहित किये हुये हैं। सरकार द्वारा लोककला संग्राहलयों, सांस्कृतिक केन्द्रों, लोकसंगीत नाटक अकादमी तथा लोककला वीथिका की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों में इन विलुप्त हो रही लोककलाओं के प्रति जागरूकता पैदा हो सके तथा साथ-साथ इसका भी ख्याल रखा जाना आवश्यक है कि बड़ी तेजी से उभरते महानगरीय संस्कृति की चकाचौंध का प्रभाव इन लोककलाओं पर न पड़े। लोककलाओं तथा इन्हीं के जैसे ग्रामीण विधाओं को आज व्यवसाय का माध्यम बनाने हेतु भी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है जिससे इन विधाओं से जुड़े लोककलाकारों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो सकेंगे तभी देश का सही मायने में विकास हो पायेगा।

देश की कला, संस्कृति, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र के कई मूल प्रश्न अभी भी अधूरे हैं अगर देश की मीडिया जिसे कि देश का चौथा स्तंभ का दर्जा प्राप्त है इन अधूरे प्रश्नों को समाचार-पत्र, पत्रिकाओं और विभिन्न मीडिया के माध्यम से समाज व सरकार के ध्यान में लाने हेतु किये गये सार्थक प्रयास से देश व समाज के विकास को एक नई दिशा प्राप्त होगी। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि देश व समाज के विकास में मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, शिवबहाल, विकास का समाजशास्त्र, प्रकाशन वर्ष 2010.
2. सिंह, जे. पी., समाजशास्त्र एक परिचय, प्रकाशन वर्ष 2010.
3. <https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0>
4. <https://hi.vikaspedia.in/social-welfare/92a90291a93e92f924940-93093e91c-93594d92f93593894d92593e/92a90291>

